भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1785
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज/इंटरनेट पहुंच

1785. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और इंटरनेट पहुँच की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत 4जी/5जी टावर स्थापित करने में देरी हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) तमिलनाडु के पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) तमिलनाडु राज्य के 16,488 गाँवों (भारत के महारजिस्ट्रार के आँकड़ों के अनुसार) में से 16,483 गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। इनमें से 16,431 गाँवों में 4जी मोबाइल कवरेज है जिसमें ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं।

सेवा से वंचित आबादी वाले गांव के लिए तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा मोबाइल कवरेज प्रदान की जाती है। सरकार डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से प्राप्त वित्तपोषण के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। जून 2025 तक, डीबीएन द्वारा वित्त पोषित मोबाइल स्कीमों के अंर्तगत तमिलनाडु में 256 टावर चालू किए गए हैं जो 300 गाँवों को 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान कर रहे हैं।
भारतनेट परियोजना को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु चरणबद्ध

तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए अनुमोदन दिया है जिसमें मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करना और मॉग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गैर-जीपी गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल हैं। जून 2025 तक, देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,325 जीपी को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें तमिलनाडु की 10,298 ग्राम पंचायतें (जीपी) शामिल हैं।

****